

## आधुनिक भारत की खुशहाली का लक्ष्य—E प्रशासन

### सारांश

ई-तकनीक ने आधुनिक मानव समाज की व्यापक होती मूलभूत आवश्यकताओं और सुखद भविष्य की कल्पना के बीच असीमित अपेक्षाओं के पुल बांध दिये हैं। इस कार्य में इण्टरनेट की बाधा सबसे अधिक है। भारत को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का स्वप्न गाँधी के 'ग्राम स्वराज' से लेकर आधुनिक समय के 'स्मार्ट विलेज' तक की यात्रा तय कर रहा है। प्रारम्भ में ई तकनीक का प्रयोग बहुत कम लोग करते थे परन्तु धीरे-धीरे सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को ई तकनीक का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में ई तकनीक का प्रयोग हो रहा है। इसका मुख्य कारण नगरीय क्षेत्र में नेट सम्बन्धी सुविधाएँ अधिक हैं। अब देखना यह है कि ई-प्रशासन से मिलने वाले फायदे को भारत के नागरिक सही रूप से प्राप्त कर सकेंगे।

**मुख्य शब्द** : ई-तकनीक, स्मार्ट विलेज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।

### प्रस्तावना

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए शासन की प्रक्रियाओं का पूर्ण रूपांतरण ई-गवर्नेंस कहलाता है। भारत में ई-गवर्नेंस उपायों को 1990 के दशक के मध्य में व्यापक आयाम मिला, जब व्यापक क्षेत्रगत अनुप्रयोग शुरू किये गये और नागरिक-केन्द्रित सेवाओं के वितरण की दिशा में अधिकतम उपायों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाने पर नीतिगत बल मिला। कई राज्यों ने महत्वाकांक्षी ई-गवर्नेंस परियोजनाएँ प्रारम्भ की जिनका उद्देश्य नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक सेवायें प्रदान करना है।

ई-गवर्नेंस संबंधी परियोजनाओं को सेवा प्रदान करने की दृष्टि से इन्हें पाँच श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

1. जी0टू0जी0 (सरकार से सरकार तक):— जब सरकार के किसी विभाग का दूसरे किसी विभाग से E-Governance के माध्यम से सम्पर्क होता है तो यह श्रेणी गवर्नेंस टू गवर्नेंस कहलाती है।
2. जी0टू0सी0 (सरकार से जनता तक):—सरकार एवं नागरिकों के बीच पारस्परिक व्यवहार गवर्नेंस टू नागरिक श्रेणी में आता है।
3. जी0टू0बी0 (सरकार से व्यवसाय तक):— गवर्नेंस टू विजनेस (व्यापार) श्रेणी के अन्तर्गत सरकार व्यापार जगत से सम्पर्क कर लेन देन करती है। जैसे—Online ट्रेडिंग तथा सीमा एवं उत्पाद शुल्क संबंधी प्रकरण आदि।
4. जी0टू0ई0 (सरकार से कर्मचारी तक):— इसमें सरकार अपने कर्मचारियों से संप्रेषण करती है।
5. सी0टू0सी0 (नागरिक से नागरिक तक):— नागरिक टू नागरिक श्रेणी में नागरिकों का पारस्परिक सम्पर्क होता है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2006 में शुरू की गयी थी। इसका लक्ष्य सभी सरकारी योजनाओं को आमजन तक पारदर्शिता और विश्वासनीयता के साथ पहुँचाना है। शुरू में मिशन मोड के अन्तर्गत 31 सेवाएँ शामिल की गयी जो कृषि, भूमि, रिकार्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा, पासपोर्ट, पुलिस अदालतें नगर पालिकाएँ, वाणिज्यिक कर, ट्रेजरी सेवाएँ आदि से सम्बन्धित थी इनमें से सभी सेवायें शुरू की जा चुकी हैं तथा लोगों को उनसे सेवायें मिलनी शुरू हो चुकी हैं। ई-प्रशासन से दो प्रकार के लाभ मिल रहे हैं—

### आर्थिक लाभ

ग्रामीण वर्ग के युवकों को रोजगार सम्बन्धी जानकारी देकर, किसानों को उनकी उपज की कीमत देकर, उत्पादन में बढ़ोत्तरी करके आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है।



**राम शंकर पाण्डेय**

असिस्टेंट प्रोफेसर,  
अर्थशास्त्र विभाग,  
एस0 एस0 (पी0जी0) कॉलेज,  
शाहजहाँपुर

**सामाजिक लगभग**

ग्रामीण किसान ई-प्रशासन का ज्ञान प्राप्त करके कृषि, स्वास्थ्य, मौसम का पूर्वानुमान, फसल प्रणाली, शिक्षा, वित्त एवं बीमा और सरकारी निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी आदि की जानकारी प्राप्त कर लाभ लेता है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

ई-प्रशासन योजना के सम्बन्ध में शोध अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं-

1. प्रत्येक नागरिक के लिए मूलभूत सेवा के रूप में डिजिटल ढाँचा।
2. केन्द्र एवं राज्यों के मौजूदा आई सीटी कार्यक्रमों का सही उपयोग एवं उनको एकीकृत करना।
3. जिला प्रशासन के आन्तरिक प्रक्रियाओं का स्वचालन तथा सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार मिटाना।
4. आईटी सक्षम व्यवस्था, परिचालन के लिए सरकारी एजेंसियों विभागों की मानव संसाधन क्षमता का विकास करने व नागरिकों अच्छी एवं पारदर्शी सेवाएँ उपलब्ध कराना।
5. भारत के नागरिकों को अधिक से अधिक इण्टरनेट के प्रयोग पर बल।

ई-प्रशासन सरकार नागरिकों के बीच सेतु कार्य करता है इसकी सहायता से शासन की नीतियाँ-योजनाएँ आमजन तक पहुँचती है। इसके लिए भारत सरकार अरबों रुपये खर्च कर रही है। ग्रामीण भारत के निर्धन लोगों को उनकी निर्धनता निश्चरता, ई-प्रशासन काफी हद तक सफल हुआ है। ग्रामीण भारत में जो सकारात्मक विकास एवं परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें ई-प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है-

“ई-गवर्नेंस हमारे डिजिटल भारत के स्वप्न का आवश्यक अंग है, हम गवर्नेंस में जितनी अधिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, भारत के लिए यह उतना ही बेहतर होगा।”

-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के कुछ घटक निम्न हैं जिससे-ग्रामीण विकास में तेजी से वृद्धि हुई।

**आईसीटी तकनीक-सूचना संचार प्रौद्योगिकी का कृषि में प्रयोग**

कृषि में उत्पादन को बढ़ाने हेतु सूचना एवं संचार आधारित तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। बेव आधारित 'केवीके' के पोर्टल भी बनाए गए हैं। आईसीटीएआर के संस्थानों के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए आईसीटीएआर पोर्टल और कृषि शिक्षा से सम्बन्धित उपयोगी सूचनाएँ प्रदान करने के लिए एग्री यूनिवर्सिटी पोर्टल को विकसित किया गया हो इसके अतिरिक्त मोबाइल एप भी किसान को त्वरित सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए बनाये गये हैं।

**किसान पोर्टल**

इस साइट पर पहुँचकर, बीज, खाद, कीटनासकों, फार्म मशीन, मौसम, खेत उत्पादों के बाजार मूल्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के पैकज, बीमा, भंडारण, ऋण एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी स्थानीय भाषा में प्राप्त कर सकते हैं यह सुविधा देश के सभी राज्यों में ब्लाक स्तर पर उपलब्ध है।

**ई-चौपाल**

इसकी स्थापना जून 2000 में ITC के कृषि व्यवसाय ने की थी। किसानों को दलालों और बिचौलियों की अवसरवादी कार्य प्रणाली से बचाने के लिए यह उन्हें कृषि यंत्रों मौसम, फसल और अन्य सम्बन्धित विषयों के बारे में सूचनाएँ प्रदान करता है। वर्तमान में 11 राज्यों 42 हजार गांवों में तकरीबन 7000 ई-चौपालों का फायदा लगभग 40 लाख किसान उठा रहे हैं। देश में सर्वप्रथम आई टीसी ने 1500 ई-चौपाल नेटवर्क बनाया है। ई-चौपाल को अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। इसे अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल चुकी है।

**एम किसान पोर्टल**

इस पोर्टल पर कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा लाखों किसानों को परामर्श दिया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 100 कृषि विज्ञान केन्द्रों पर स्वचालित मौसम केन्द्र जोड़े गये हैं।

**ई नैम पोर्टल की स्थापना**

किसानों को उनकी उपज का अधिकतम लाभ देने, पूरे देश में कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नैम) की शुरुआत 200 करोड़ रुपये के प्रारंभिक आवंटन के साथ इस योजना का 1 जुलाई 2015 को अनुमोदन किया गया था। इसमें अब तक 13 राज्यों की 419 मंडियों को ई-नाम के साथ एकीकृत किया गया यह पोर्टल हिन्दी और अंग्रेजी के साथ अधिकांश क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। 14 अप्रैल 2016 को अम्बेडकर जयन्ती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा राष्ट्रीय कृषि मंडी, वेब आधारित ऑनलाइन व्यापार पोर्टल की शुरुआत की गयी। 8 जून 2017 तक 13 राज्यों की 419 मंडियाँ, 46 लाख किसान, 90,000 व्यापारी एवं 47000 कमीशन एजेंट ई-नाम पोर्टल से जुड़ चुके हैं। जिनके द्वारा 22179 करोड़ रुपये की राशि से 96 लाख मीट्रिक टन उत्पादों का कारोबार किया जा चुका है इसके लिए टोल फ्री नं०1800-2700-224 पर हेल्प डेस्क स्थापित व चालू किया गया है।

**किसान काल सेंटर**

किसान अपनी फसल से सम्बन्धित किसी भी समस्या के समाधान के लिए 'किसान काल सेंटर' की सुविधा सभी राज्यों में उपलब्ध है। जिसमें किसान अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं जिसका समाधान 24 घंटे के अन्दर कृषि विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। जिसका टोल फ्री नं० 1800-180-1551 पर साल के 365 दिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।

**सूचना संचार प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में प्रयोग****टेली मेडिसिन**

स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी से काफी उन्नति हुई है। इंटरनेट के माध्यम से आज मरीज देश के ही नहीं विदेशों के विशेषज्ञों से सम्पर्क साधा जा सकता है। अपोलो अस्पताल इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण भारत के लाखों लोगों को उच्चस्तरीय, विशेषज्ञता

वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। 'मेड-इटेग्रा' साफ्टवेयर का उपयोग करके डॉक्टर एवं मरीज एक दूसरे से बात कर सकते हैं। यह विभिन्न राज्यों में 400 से अधिक टेली मेडिसिन केन्द्रों का संचालन करता है।—60 हजार से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। न्यूरोसर्जरी से लेकर बाल हृदय विज्ञान के बारे में 13,500 से अधिक मामलों में टेली परामर्श सफलतापूर्वक दिये जा चुके हैं।

जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के क्षेत्र में भी इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है। रेडियों, टेलीविजन, केवल नेटवर्क तथा बड़े परिवार की हानियों से अवगत कराया जा रहा है। एडस जैसी घातक बीमारी से बचने के उपायों इसके लक्षणों इत्यादि के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ मलेरिया, कुष्ठ, तपेदिक, डिफ्थीरिया, उत्तरांचल, हजारों, प्रणाली, बीमारी आदि रोगों के निवारण हेतु अस्पताओं का विवरण इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ भी अब मिलना शुरू हो गया है। ग्रामीण जनता अब धीरे-धीरे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने लगी है।

### दृष्टि

दृष्टि पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, मणिपुर अरुणाचल, समेत 12 राज्यों में कार्यरत है। इनमें बिहार उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा और तमिलनाडु भी शामिल हैं। यह ई-प्रशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने वाली ग्रामीण नेटवर्किंग और विपणन सेवाओं के लिए राजस्व अर्जित करने वाले मंच के रूप में काम करती है। यह ई-कॉमर्स और कृषि व्यापार के माध्यम से नागरिकों को ऑनलाइन क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान करती है। दृष्टि देश के उत्तरी और पूर्वी राज्यों में—हजार गुमटियों का संचालन करती है। इसको विश्व आर्थिक मंच का टेक्नोलॉजी पायोनियर्स पुरस्कार, वर्ष का सामाजिक उद्यमी पुरस्कार, अशोका फाउंडेशन फेलोशिप पुरस्कार, डेवलपमेंट मार्केट प्लेस पुरस्कार, सर्वोत्तम आई सी0टी0 कथा पुरस्कार, सर्वाधिक संभावनाओं वाला सामाजिक उद्यमी पुरस्कार और स्टाकहोम चैलेंज पुरस्कार जैसे अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।

### परिवाहन क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग

#### जागृति ई-सेवा

इस सेवा शुभारम्भ मार्च 2003 में हुआ था। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वित्तीय, यात्रा और ई-प्रशासन से लेकर संचार सेवा तक प्रदान करती है। समूची प्रणाली प्रणाली अविलंब किसी भी भाषा में बदली जा सकती है। मार्गदर्शक, सूचना और कृषि संबन्धी जानकारियाँ देने के अलावा यह केन्द्र राजस्व अर्जित करने के लिए मोबाइल फोन और बस टिकट की बिक्री बीना पैसे का हस्तांतरण और अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है। जागृति नेटवर्क के जरिए ई-मेल को घर तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। चूंकि यह सेवा गाँव केन्द्रित है इसलिए इसे आइ0टी0 जनित ग्रामीण सेवा भी कहते हैं। इस परियोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य हजारों ग्रामीण युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना है।

रेलवे तथा वायुयान मार्ग के टिकटों को ऑन लाइन बुक करवाया जा सकता है। तथा यात्रा रद्द करने पर टिकटों को निरस्त भी कराया जा सकता इसके अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्र में भी टिकट बुक से लेकर कमरा, टैक्सी आदि कार्य करवाये जा सकते हैं।

### शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग

शिक्षा के विस्तारीकरण के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी अत्यन्त सार्थक है। 20 सितम्बर 2004 को भारत द्वारा पहला शैक्षिक उपग्रह एडुसैट अन्तरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर ग्रामीण शिक्षा क्षेत्र में विशाल कार्य किया गया। इस उपग्रह की सहायता से विभिन्न भारतीय भाषाओं को अनुवाद स्थानीय भाषा में प्राप्त किया जा सकेगा। यह प्रणाली प्रतिक्रियात्मक सुविधाओं से युक्त है अर्थात् विद्यार्थी एक साफ्टवेयर की सहायता से दूर स्कूलियों में बैठे शिक्षक से न केवल प्रश्न कर सकेंगे बल्कि उसका उत्तर भी प्राप्त कर सकेंगे।

मानव संसाधन मंत्रालय के तहत नवोदय विद्यालय समिति ने 2013 में दक्षिण कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी सैमसंग के साथ मिलकर स्मार्ट क्लास की शुरुआत की। आज ग्रामीण इलाकों के करीब 400 जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 लाख से अधिक छात्र स्मार्ट क्लास के जरिये आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कम्प्यूटर साइंस, अंग्रेजी, गणित विषयों के लर्निंग एप तैयार किए गए हैं। छात्रों को वीडियो एमिनेशन, और प्रजेंटेशन जैसे माध्यमों से इंटरैक्टिव मॉड्यूल का इस्तेमाल कर शिक्षा दी जा रही है।

डिजिटल इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में एक ई-क्रान्ति है जिसके अन्तर्गत शिक्षा के क्षेत्र में ई-टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रामीण भारत को डिजिटाइज करने पर बहुत जोर दिया है। ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ कार्यक्रम निम्न हैं—

1. ई-बस्ता
2. राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एन0 डी0 एल0 एम0)
3. प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
4. डिजिटल क्लासरूप
5. ऑनलाइन शिक्षा
6. शिक्षकों की वायोमेट्रिक उपस्थिति
7. स्कूलों में निशुल्क वाई-फाई
8. डिजिटल पुस्तकालय

#### जनसेवा केन्द्र

ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये ऐसे केन्द्र जहाँ सभी प्रकार के जरूरी फार्म कम्प्यूटर की मदद से भरा जाता है। जन सेवा केन्द्र का मुख्य उद्देश्य बिना भ्रष्टाचार के गरीब लोगों की मदद करना है। भारत सरकार ने हर जिलों और हर शहर में कम से कम 5 कि0 मी0 की दूरी पर जन सेवा केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है Digital India Initiative के तहत भारत सरकार ने पूरे भारत में करीब 1 लाख सी0 एस0 सी0 केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है। इन केन्द्रों पर राशन कार्ड, पेंशन, बीमा, जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार कार्ड, पेनकार्ड, वोटर कार्ड,

पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल रिचार्ज, डी0टी0एच0 रिचार्ज मोबाइल बिल, मनीट्रांसफर, एल0 आई0 सी0 की किस्त तथा पैसे के लेनदेन भी किया जाता है।

#### मौसम सम्बन्धी जानकारी

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग मौसम, बातावरण, कृषि तथा भूमि सम्बन्धी स्थानीय आंकड़ों के एकीकरण तथा समायोजन में किया जा रहा है। आर्द्र भूमि, मानचित्रिकरण, सूखा तथा बाढ़ पर्यवेक्षण, पर्यावरणीय परिवर्तन तथा इसके प्रभाव इत्यादि कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का बड़ा महत्व है। सूखा, बाढ़ भूकम्प जैसी आपदाओं से प्रबन्धन में इस तकनीक का बड़ा योगदान है। इस प्रकार की सूचनाओं को एकीकृत स्वरूप को भौगोलिक सूचना पद्धति कहते हैं। इसके अंतरगत तकनीक प्राप्त सूचनाओं, चित्रों आकड़ों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सम्प्रेषण किया जाता है जिसका लाभ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को मिलता है।

#### निष्कर्ष

आज आजादी के 70 वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, जागरूकता, तथा शिक्षा का लाभ पहुंचाने वाली एक सर्वग्राही, सर्वसुलभ तथा सस्ती प्रणाली के रूप में स्थापित हो चुकी है। स्थानीय लोगों के समाधानों का अदान-प्रदान कर कृषि एवं बाजार आदि से जुड़ी सूचनाओं के द्वारा आई0 सी0 टी0 ग्रामीण क्षेत्र का परिदृश्य बदलने का कार्य कर रही है। डिजिटल ग्रामीण शिक्षा न केवल उद्यमिता का सूत्रपात करती है और गाँवों में गरीबी उन्मूलन, महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संचार साधनों का विकास हुआ है। ई-प्रशासन के माध्यम से इसका प्रसार भी हुआ है। किन्तु आज भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ई-प्रणाली से लोग अपरिचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके और अधिक प्रचार प्रसार की जरूरत है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी का लाभ प्रत्येक गाँव को मिले इस दिशा में प्रयास नितांत आवश्यक है। और यह सब दृढ़ इच्छाशक्ति तथा सकल्प के बिना सम्भव नहीं है। गाँवों में बसने वाला भारत अब ई-ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड डिजिटल इंडिया परियोजना की सभी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरी कर देगी। मौजूदा भारत सरकार इस बात को समझती है कि अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए यह पहल सभी नागरिकों तक इंटरनेट सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर भारत को एक सम्पूर्ण डिजिटल और सशक्त अर्थव्यवस्था बनाने में रीढ़ का काम करेगी।

#### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ऑनलाइन एजुकेशन इन इण्डिया 2021 /
2. [www.echupal.com](http://www.echupal.com)
3. [www.Jagriti.com](http://www.Jagriti.com)
4. [www.telemedeonsult.Com](http://www.telemedeonsult.Com).
5. [www.akashganga.In](http://www.akashganga.In)
6. [www.sitapur.Nic.inelokvani Imelokvani](http://www.sitapur.Nic.inelokvani Imelokvani)
7. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका
8. योजना मासिक पत्रिका
9. दैनिक समाचार पत्र
10. अमर उजाला समाचार पत्र
11. [www.enam.gov.in](http://www.enam.gov.in)
12. [www.Jan.sevakendra.Com](http://www.Jan.sevakendra.Com).